नाम में क्या रखा है? : 'दलित' शब्द के उपयोग पर

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-I (भारतीय समाज) से संबंधित है।

06 सितम्बर, 2018

द हिन्दू

''हमें यह समझना चाहिए कि 'दलित' शब्द आत्म-सशक्तिकरण का भाव है।''

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सलाहकार ने मीडिया को सलाह दी कि वे 'दलित' शब्द का उपयोग करने से बचे। साथ ही केंद्र ने राज्य और केंद्र सरकार के विभागों से सरकारी कामकाज और दस्तावेजों में अनुसूचित जाति से जुड़े सभी लोगों के लिए 'दलित' शब्द का इस्तेमाल करने से बचने का निर्देश दिया है।

सामाजिक न्याय मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को 10 फरवरी, 1982 को जारी गृह मंत्रालय के एक निर्देश का हवाला देते हुए अधिकारियों को अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र में 'हरिजन' शब्द को सम्मिलित न करने को कहा है।

देखा जाये तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से मीडिया को 'दलित' शब्द का इस्तेमाल बंद करने के लिए निर्देश जारी करने पर विचार करने को कहा था, जिसके बाद सरकार ने इसे मान लिया। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कोर्ट ने सरकार को सिर्फ विचार करने के लिए कहा था, बिना विचार किये इस पर अमल करने के लिए नहीं कहा था।

यहाँ सरकार को अपने इस फैसले को वापस लेना चाहिए, क्योंकि उन्हें यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि मीडिया अपना कार्य कैसे करे। बेशक, अनुसूचित जातियों के सदस्यों को संदर्भित करने के लिए 'दलित' शब्द का उपयोग करने के औचित्य पर बहस नई है।

एक दशक पहले, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने 'दलित' शब्द के उपयोग को खारिज कर दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि यह असंवैधानिक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 'अनुसूचित जाति' से संबंधित संविधान के अनुच्छेद-341 के तहत राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित सूची में नामित जातियों के सदस्यों पर प्रदान की गई कानूनी स्थिति है। इसलिए, तर्कसंगत रूप से, 'अनुसूचित जाति' आधिकारिक संचार और दस्तावेजों में लोगों के इस वर्ग को संदर्भित करने का उचित तरीका है।

हालांकि, मीडिया में और गैर-आधिकारिक संदर्भों में 'दलित' शब्द के उपयोग का विरोध करना भी उचित नहीं है - एक नामकरण जिसे समुदाय द्वारा चुना जाता है और उपयोग किया जाता है। शब्द समय के साथ विकसित हुआ है और विभिन्न संदर्भों में आत्म-सम्मान, दावे, एकजुटता और जाति उत्पीड़न के विरोध में विभिन्न चीजों का प्रतीक बन गया है।

अतीत में, दलितों को 'अछूत' कहा जाता था, लेकिन ब्रिटिश शासन के दौरान आधिकारिक शब्द 'उदास वर्ग' था। महात्मा गांधी ने 'हरिजन' या 'भगवान के बच्चे' शब्द का उपयोग करके इस कलंक को हटाने की कोशिश की। समय के साथ, समुदाय ने इस अपील को खारिज कर दिया।

जिसके कुछ दशक बाद ही उन्होंने खुद को दलितों के रूप में संदर्भित करना शुरू कर दिया। 'दलित' का शाब्दिक अर्थ है- पीड़ित, शोषित, दबा हुआ, खिन्न, उदास, टुकड़ा, खंडित, तोड़ना, कुचलना, दबा हुआ, पिसा हुआ, मसला हुआ, रौंदा हुआ, विनष्ट आदि है, साथ ही यह शब्द इनकी पहचान को दोबारा शुरू करने के लिए एक समुदाय के संघर्ष को भी दर्शाता है।

* * *

इससे संबंधित तथ्य

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से सभी प्राइवेट न्यूज चैनलों को सलाह दी गई है कि वे अपनी रिपोर्टों में 'दलित' शब्द की जगह संविधान में दिए गए 'अनुसूचित जाति' शब्द का इस्तेमाल करें।
- हालांकि इस पर विवाद खड़ा हो गया है। टीवी चैनलों के प्रमुखों के बीच इसे लेकर सहमति नहीं दिख रही है।
- न्यूज ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशन (NBA) के कुछ सदस्यों ने भी पिछले कुछ दिनों में इन नियमों का विरोध किया है।

पृष्ठभूमि-

- साल 1972 में महाराष्ट्र में दलित पैंथर्स मुंबई नाम का एक सामाजिक-राजनीतिक संगठन बनाया गया। आगे चलकर इसी संगठन ने एक आंदोलन का रूप ले लिया।
- नामदेव ढसाल, राजा ढाले और अरुण कांबले इसके शुरुआती प्रमुख नेताओं में शामिल हैं। इसका गठन अफ्रीकी-अमेरिकी ब्लैक पैंथर आंदोलन से प्रभावित होकर किया गया था।
- यहीं से 'दलित' शब्द को महाराष्ट्र में सामाजिक स्वीकृति मिल गई। लेकिन अभी तक दलित शब्द उत्तर भारत में प्रचलित नहीं हुआ था।
- भारतीय जनगणणा 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या में लगभग 16.6 प्रतिशत या 20.14 करोड़ आबादी दलितों की है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

- यह एक स्वायत्त संस्था है। भारतीय संविधान के मूल अनुच्छेद 338 के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था।
- यह उनकी सामाजिक एवं आर्थिक विकास, सरकारी सेवा का संरक्षण एवं अत्याचार निवारण के कार्यो की देख-रेख और जाँच-पड़ताल करता था और राष्ट्रपति को अपनी वार्षिक रिपोर्ट अथवा बीच में भी कोई रिपोर्ट प्रस्तुत करता था।
- वह विशेष अधिकारी एक सदस्यीय आयोग था, जिसे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आयुक्त के नाम से पदनामित किया गया था।
- इसका कार्यकाल पाँच वर्ष का होता था और इस पर सामान्यत: तत्कालीन सेवानिवृत्त कल्याण सचिव, भारत सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के किसी ख्यात व्यक्ति को आयुक्त (एक सदस्यीय आयोग का अध्यक्ष) बनाया जाता था।

अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम

- इसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अत्याचारों की रोकथाम के लिये लाया गया था।
- यह अधिनियम मुख्य अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम,1989 का संशोधित प्रारूप है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. यह एक स्वायत्त संवैधानिक संस्था है।
2. यह तीन सदस्यीय आयोग है, जिसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

2. निम्नलिखित में भारतीय संविधान का अनुच्छेद-338 के संबंध में क्या सत्य है?

(a) इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है।
(b) इसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है।
(c) इसके अंतर्गत पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है।
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

1. Consider the following statements regarding National Scheduled Caste Commission-

1. This is an autonomous, constitutional body.
2. This is a three membered commission, whose Chairperson is appointed by the President.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1 (b) Only 2
(c) Both 1 and 2 (d) Neither 1 nor 2

2. Which of the following statements is/are correct regarding Acticle 338?

(a) Scheduled Caste Commission was established under this article.
(b) Under this article Scheduled Tribe Commission is established.
(c) Under this article Backward Class Commission is given Countitutional states.
(d) None of the above

नोट :

05 सितम्बर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(c), 2(a) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. हाल ही में एक विशेष समुदाय को इंगित करने वाला शब्द 'दलित' के प्रयोग पर बहस छिड़ी हुई। क्या इस शब्द का प्रयोग बंद करवा देना चाहिए? आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। (250 शब्द)

Recently a debate has erupted on the use of a word 'Dalit' derogating a specific community. Should the use of this word be abolished? Critially evaluate. (250 Words)